

भारत में हाई-एंड उत्पाद: दशा और दशिया

यह एडिटरियल 21/09/2021 को 'द हट्टि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित "How to boost export of high-end products" लेख पर आधारित है। इसमें भारत के हाई-एंड उत्पादों (High End Products) के निर्यात की स्थिति और इनके उत्पादन से संबद्ध समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था काफी लंबे समय तक कृषि क्षेत्र पर निर्भर रही। इस समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से भी अधिक था। समय के साथ भारत धीरे-धीरे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में परिणत हो गया। हालाँकि कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि माध्यमिक क्षेत्र की अनदेखी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह तेज़ी से विकसित नहीं हो सकी है।

बीते कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा वनिरिमाण क्षेत्र पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वनिरिमाण क्षेत्र के महत्त्व और रोज़गार सृजन में इसकी क्षमता को समझते हुए वर्तमान सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

हालाँकि, कई जानकार मानते हैं कि उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के लिये वनिरिमाण को 'लो-एंड' से 'हाई-एंड' उत्पादों की ओर स्थानांतरित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

हाई-एंड उत्पाद निर्यात की मौजूदा स्थिति

- अध्ययन की सुविधा के लिये हम निर्यातित उत्पादों को दो श्रेणियों या बास्केट में विभाजित कर सकते हैं- बास्केट 'A' और बास्केट 'B'।
- बास्केट 'A' में वे उत्पाद शामिल हैं जिनका विश्व स्तर पर बड़े मूल्यों में कारोबार किया जाता है, लेकिन जसिमें भारत की हसिसेदारी काफी कम है। उदाहरण के लिये मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और परिवहन उत्पाद वैश्विक माल निर्यात बास्केट के 37% हसिसे का निरिमाण करते हैं।
 - लेकिन इनमें से प्रत्येक के वैश्विक निर्यात में भारतीय निर्यात की हसिसेदारी बेहद कम है।
 - भारत मशीनरी में 0.9%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 0.4% और परिवहन उत्पादों में 0.9% की हसिसेदारी रखता है।
 - कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादों जैसे- इंटीग्रेटेड सर्किट (0.03%), कंप्यूटर (0.04%), सोलर-सेल (0.3%), एलईडी टीवी (0.02%), मोबाइल फोन (0.9%) में भी भारत की हसिसेदारी काफी कम ही है।
- बास्केट 'B' में वे उत्पाद शामिल हैं जिनके वैश्विक निर्यात में भारत बड़ी हसिसेदारी है, लेकिन इन उत्पादों में विश्व व्यापार का मूल्य काफी नमिन है।
 - उदाहरण के लिये वैश्विक वस्त्र निर्यात में भारत की हसिसेदारी 5.9% है, कति वस्त्र एक बहुत छोटी श्रेणी है, जसिकी वैश्विक निर्यात बास्केट में मात्र 1.3% हसिसेदारी है।
 - इसी प्रकार, समुद्री उत्पादों में भारत की हसिसेदारी 5.4% है, लेकिन वैश्विक निर्यात बास्केट में समुद्री उत्पादों की हसिसेदारी मात्र 0.6% है।
 - ऐसे ही कई अन्य उदाहरण हैं, जहाँ वैश्विक निर्यात मूल्य नमिन है, लेकिन भारत के पास उनमें एक बड़ी हसिसेदारी है। उदाहरण के लिये कटे और पॉलिश किये गए हीरे (28.8%), आभूषण (13.5%), चावल (35%), इींगा (25.4%) और चीनी (12.4%) आदि।
- 'निर्यात जटलिता सूचकांक' (Export Complexity Index- ECI)) 130 देशों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विविधता और तकनीकी परिष्करण (Technological Sophistication) को मापता है। इस सूचकांक में वर्ष 2000 में भारत की रैंक 42 और वर्ष 2019 में 43 थी, जसिका मुख्य कारण है कि बास्केट 'A' उत्पादों के मामले में भारत की स्थिति किमज़ोर है।
 - इसी अवधि में बास्केट 'A' उत्पादों में वसितार के कारण चीन की रैंक 39 से सुधरकर 16 हो गई है।
 - ऐसे में भारत को बास्केट 'A' के उत्पादों के मामले में अपनी उपस्थिति बिढाने पर विशेष बल देना चाहिये।
- दूसरी ओर बास्केट 'B' का छोटा आकार विकास क्षमता को सीमित करता है। इस श्रेणी के अधिकांश उत्पाद शर्म-गहन और नमिन प्रौद्योगिकी वाले हैं, जनिहें कम-लागत वाले देशों से प्रतसिपर्द्धा का सामना करना पड़ता है।

भारत में वनिरिमाण से संबद्ध समस्याएँ

- **अपर्याप्त कुशल कार्यबल:** वनरिमाण क्षेत्र को अपने विकास के लिये आवश्यक कौशल एवं प्रशिक्षण से संपन्न एक शक्ति कार्यबल की आवश्यकता है।
 - भारत में कौशल पारितंत्र को दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता है।
- **आधारभूत अवसंरचना:** वकिसति देशों की तुलना में भारत में वनरिमाण प्रयोगशालाओं, कनेक्टविटी और परविहन की स्थिति मंद एवं अधिक लागतपूर्ण है जो उद्योगों के लिये एक बड़ी बाधा है।
 - नरिबाध बजिली आपूर्ति एक अन्य प्रमुख चुनौती है।
- **लघु आकार:** लघु उद्यम अपने छोटे आकार के कारण कम उत्पादकता की समस्या से ग्रस्त हैं जो अर्थव्यवस्था को व्यापक आकार प्राप्त करने से रोकता है।
- **अनुसंधान एवं विकास पर नमिन व्यय के कारण नवाचार की कमी:** वर्तमान में भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% ही अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च करता है जो अन्य वकिसति देशों की तुलना में बेहद कम है।
 - यह नवाचार क्षमता और विकास को अवरुद्ध करता है।
- **नमिन उत्पादकता:** भारत में शर्म उत्पादकता और पूंजी उत्पादकता- दोनों ही काफी नमिन हैं। भारत की तुलना में इंडोनेशिया की वनरिमाण उत्पादकता लगभग दोगुनी है, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया की उत्पादकता चार गुना अधिक है।
 - आँकड़ों के मुताबिक, दक्षिण कोरिया का इलेक्ट्रॉनिक्स वनरिमाण क्षेत्र भारत की तुलना में 18 गुना अधिक उत्पादन करता है और दक्षिण कोरिया का रसायन नरिमाण क्षेत्र भी 30 गुना अधिक उत्पादक है।

हाई-एंड उत्पाद नरियात बढ़ाने के उपाय

- **इनपुट पर नमिन आयात शुल्क अधरिपति करना:** इनपुट पर उच्च शुल्क के परिणामस्वरूप तैयार उत्पाद काफी महँगे होते हैं, जिसके कारण वे घरेलू और नरियात बाजार दोनों में आयातित वस्तुओं से मूल्य-प्रतस्पर्द्धा में पछिड़ जाते हैं।
 - नमिन शुल्क घरेलू फर्मों को प्रतस्पर्द्धा बनाएंगे और जल्द ही इनमें से कई प्रत्यक्ष शपिगि शुरू कर सकेंगी।
 - समय के साथ बेहतर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लकिंज के साथ, नरियात और आयात दोनों क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ रोजगार अवसरों की वृद्धि होगी।
 - उदाहरण के रूप में वयितनाम को देखा जा सकता है, जहाँ 5 मिलियन कामगार प्रत्यक्ष रूप से नरियातकों के साथ संलग्न हैं, जबकि 7 मिलियन कामगार इन नरियातकों को उत्पादों की आपूर्ति करने वाली फर्मों के लिये कार्य कर रहे हैं।
- **औपचारिक वित्त तक पहुँच में वृद्धि करना:** शीर्ष दस लाख छोटी वनरिमाण फर्मों को नयिमति ब्याज दरों पर किसी संपारश्वकि के बनिा बैंक वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाना आवश्यक है।
 - भारत की छोटी फर्मों के पास मात्र 4% औपचारिक वित्त तक पहुँच है। अमेरिका, चीन, वयितनाम और श्रीलंका के लिये यह आँकड़ा 21% है।
- **नमिन मूल्य उत्पादों की नरियात प्रक्रिया को सरल बनाना:** बहुत से लोग स्थानीय स्तर पर उत्पादित साड़ी, सूट, हस्तशिल्प, तैयार/पके हुए खाद्य उत्पाद की खरीद करते हैं और उन्हीं दुकानों से वदिश में अपने मतिरों और परजिनों तक इन्हें कुरियर किये जाने की अपेक्षा रखते हैं।
 - ऐसे नमिन मूल्य के उत्पादों के नरियात के लिये सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, वदिश व्यापार महानदिशालय (DGFT) और अन्य संबद्ध एजेंसियों से संबंधित अनुपालनों को सरल एवं एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है।
 - ऐसे सरलीकरण से ज़िलों को 'नरियात हब' के रूप में वकिसति कयिा जा सकेगा।
 - इस सरलीकरण से क्लास 'B' और 'C' शहरों में कार्यरत छोटे कारीगरों और फर्मों को भी अपने माल के नरियात में मदद मिलेगी।
- **महत्त्वपूर्ण उत्पादों से संलग्न बड़ी प्रमुख फर्मों को भारत में अपना परिचालन शुरू करने के लिये आमंत्रित करना:** बास्केट 'A' के उत्पादों के वनरिमाण और नरियात को बढ़ावा देने के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण रणनीति है। सरल शर्म कानून, PLI प्रोत्साहन, नए वनरिमाण परिचालनों पर नमिन कॉर्पोरेट कर और पूर्वव्यापी कर को समाप्त करने जैसी सरकारी पहलों ने 'चाइना प्लस-वन' (China Plus-One) नीति का अनुसरण करने वाली कई फर्मों को भारत में अपना आधार स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहित कयिा है।
 - इस संदर्भ में बड़ी संख्या में प्रतस्पर्द्धा सहायक इकाइयों की उपस्थिति और कौशल आधार भारत को अन्य प्रतस्पर्द्धा देशों की तुलना में अधिक अनुकूल बनाता है।
- **उत्पादकता बढ़ाना:** वैश्विक स्तर पर प्रतस्पर्द्धा बनने के लिये भारत की वनरिमाण मूल्य शृंखलाओं को अपनी उत्पादकता को वैश्विक मानकों के करीब लाना होगा।
 - प्रमुख वनरिमाण प्रक्रियाओं में सुधार करने से चयनित मूल्य शृंखलाओं में भारतीय कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।
 - उद्योग 4.0 एवं स्वचालन प्रौद्योगिकी को अपनाकर और रि-स्कलिगि तथा अप-स्कलिगि में नविश के माध्यम से भारतीय वनरिमाता हाई-एंड उत्पादों के उत्पादन में तेज़ी ला सकते हैं।

ADVANTAGE INDIA

Robust Demand

- The appliances and consumer electronics (ACE) market in India is expected to grow to US\$ 21.18 billion by 2025 from US\$ 10.93 billion in 2019.
- As per a report by NITI Aayog and RMI India, the electric vehicles financing industry in India is projected to grow to ~ US\$ 50 billion by 2030.

Increasing Investment

- In the first half of FY21, India received ~US\$ 30 billion worth of funds through foreign direct investment, a 15% increase over the same period last year.

Policy Support

- In May 2021, the government approved a PLI scheme worth Rs. 18,000 crore (US\$ 2.47 billion) for production of advanced chemical cell (ACC) batteries; this is expected to attract investments worth Rs. 45,000 crore (US\$ 6.18 billion) in the country.
- In July 2021, the government launched six technology innovation platforms to develop technologies and thereby, boost the manufacturing sector in India to compete globally.

Competitive Advantage

- Increasing share of young working population.
- India can achieve its full manufacturing potential as it looks to benefit from its demographic dividend and a large workforce over the next two to three decades.

//



अभ्यास प्रश्न: उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के लिये वनरिमाण को लो-एंड से हाई-एंड उत्पादों की ओर स्थानांतरित करना अनविर्य है। चर्चा कीजिये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/high-end-products-in-india>

